

बल्कि 184 के तहत प्रस्ताव के रूप में और उसको सदन में लाकर और कम से कम दो दिन तक इस पर चर्चा चलाई जानी चाहिये। देश के कम से कम 52 प्रतिशत लोगों के स्तर को ऊपर उठाने का यह सवाल है। इस पर कम से कम दो दिन तक चर्चा आप चलायें यह मेरा गुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा जितनी देर कहो, उतनी देर चला देंगे। चर्चा की कोई गान नहीं।

श्री श्रीधर नारायण सिंह : पासवान जी और मेहता जी दोनों सदन की कार्यवाही को समझने वालों में से हैं और जैसा उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है—

एक माननीय सदस्य : और नहीं हैं ?

श्री श्रीधर नारायण सिंह : सभी हैं। आप तमाम माननीय सदस्य हैं।

उन्होंने जो कुछ कहा है उसके उत्तर में मैं इतना ही कहूंगा कि कार्य मंत्रणा समिति का यह सर्वसम्मति प्रतिवेदन है। सारे प्रोसीजर और सारी कार्यवाही और सब के विचार जानने के बाद वहां निर्णय होता है और उसका जो प्रतिवेदन होता है उसको मैं यहां रखता हूं। मैं न उन में संशोधन कर सकता हूं और न कोई दूसरा सुझाव दे सकता हूं।—
श्री राम बिलास पासवान : पुनर्विचार तो हो सकता है।
श्री श्रीधर नारायण सिंह : मुझे वापस करने का भी अधिकार नहीं है।

जहां तक बैम्बई क्लासिफिकेशन का रिपोर्ट का संबंध है सभी माननीय सदस्य जो वहां उपस्थित थे और आपके दल के भी थे, सभी ने एक राय करके माना है कि यह मामला ऐसा है कि इस पर वाद-विवाद होना चाहिये और 193 में हो, इसको भी माना है। उसी के मुताबिक मैं प्रतिवेदन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सभी की सहमति से यह प्रतिवेदन यहां रखा गया है। उसी को मैंने यहां पर उपस्थित किया है।

श्री राम बिलास पासवान : डिफर क्या करते सब से बड़ी बात यह है कि लोग समझ रहे हैं कि चर्चा होगी। 193 और 184 में चर्चाओं में जमीन आसमान का फर्क है। डिस्कशन का कुछ निष्कर्ष निकालना चाहिये और यह तभी हो सकता है जब 184 में करवाएं।

MR. SPEAKER : I shall now put the amendment moved by Shri Ram Vilas Paswan to the vote of the House.

The amendment was put and negatived

MR. SPEAKER : The question is :

"That this House do agree with the Thirty-fourth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 3rd August, 1982."

The motion was adopted.

12.56 hrs.

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

MATTERS UNDER RULE 377

(i) *Import of Coconut oil from Phillippines*

PROF. P. J. KURIEN (MAVELIKARA): Sir, the hon. Minister of Civil Supplies, in reply to a question, has informed this House on 19th July, 1982 that the question of import of coconut oil from Phillipines is under the consideration of the Government. Sir, this announcement is of great concern to us and is to the detriment of the coconut growers in the country, especially Kerala.

Sir, Kerala accounts for 70 per cent of the total area under coconut cultivation and 90 per cent of the copra produced in the country comes from Kerala. Nearly 3 million families of which about 90 per cent are small land holders in Kerala depend on the coconut cultivation for their livelihood.

Sir, some importers in the country had imported coconut oil in the guise of non-edible industrial oil, engine oil etc. They had processed the imported oil and sold in the market as edible oil. We had brought this matter to the notice of the Commerce Ministry and the then Commerce Minister had given us an assurance that coconut oil of any type will not be permitted to be imported.

Sir, now the Civil Supplies Minister has announced that the Government is consi-

dering the question of import of coconut oil from Phillippines. Such a step will crush the economy of Kerala and will adversely affect the 30 million coconut farmers, 90 per cent of whom are only small land holders whose sole source of income is coconut garden. Already the price is unremunerative. It should be noted that, at present, the cheapest edible oil in the country is coconut oil. If coconut oil is further imported that will be a death-blow to the coconut farmers in the country.

I, therefore, request the Government to drop any move to import coconut oil of any type and save the coconut growers in the country from being put into serious crisis.

(ii) *Declaration of certain areas of Uttar Pradesh as Tribal Areas*

श्री हरेश रावत (अल्मोड़ा) : उत्तर प्रदेश में कई जातीय समुदाय जिन्हें जनजाति का दर्जा प्राप्त होना चाहिये था, उन्हें जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। पिथौरागढ़ जनपद (उ०प्र०) के गंगोलीहाट ब्लॉक में एक ऐसी जाति कुथलिया बोरा है जिनके रिश्ते नाते, आचार-विचार, संस्कृति व उद्यम जनजाति का है लेकिन उन्हें जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। अतः शासन को पुनः सर्वेक्षण कर इस प्रकार की जातियों को जनजाति के रूप में मान्यता देनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश में ही 4 ऐसे विकास खंड हैं जिनमें उनकी कुल जनसंख्या का 30 प्रतिशत से अधिक जनजाति, 20 प्रतिशत के लगभग हरिजन व शेष ऐसी जातियों के लोग रहते हैं जो इन विकास खंडों में जनजातियों के सहयोगी जातियों के रूप में बसे थे। इन जातियों की आर्थिक व सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति लगभग वही है जो इन विकास खंडों के अन्तर्गत रहने वाली जनजातियों की है। इस प्रकार के विकास खंड धारचूला-मुनस्यारी-पिथौरागढ़ जनपद, जोशीमठ चगोली जनपद तथा यमुनाबाद देहरादून जनपद में हैं। इन क्षेत्रों की जनता लम्बे समय से इन विकास खंडों को जोनसार भाबर की तरह जनजाति क्षेत्र घोषित करने की मांग करती आ रही है ताकि यहां बसने वाली सभी जातियों को जनजातियों को प्राप्त सभी प्रकार

की सुविधायें प्राप्त हो सकें। इस हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी केन्द्र की सरकार को लिखा गया है।

अतः मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि जनजाति क्षेत्रों के सन्दर्भ में प्रेजीडेंशियल आर्डर में संशोधन कर धारचूला-मुनस्यारी, जोशीमठ व यमुनाबाद विकास खंडों को जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाए।

(iii) *Modernisation of Cuttack Station of AIR.*

SHRIMATI JAYANTI PATNAIK (CUTTACK) : The failure of AIR Station, Cuttack, to cover various programmes to its entire listening zone has caused a great discontentment among the people of that zone. All India Radio Station, Cuttack, has 8 districts under its entire zone. The transmitter installed in that station at present is not powerful enough to cover all those districts. The people of the entire State depend on this Radio Station for listening to the latest news and other entertainment/cultural programmes. But they are deprived of getting such facilities in the absence of multi-channels in that radio station.

Many of the State Radio Stations have more than one channel. One channel looks after the local needs and the other channel mostly takes over the burden of various programmes of National interest broadcast from Delhi. On one side, the cultural ethos of the State, on the other side, the development-oriented programmes would be well catered to, if there is one more channel preferably a short wave transmitter at Cuttack. That would give an alternative listening to the far-flung areas because the local V.B. Channel cannot be heard beyond 30 KM from Cuttack.

Steps have been taken by the Ministry of Information and Broadcasting to improve the radio stations of different States. Similar steps should also be taken to provide adequate radio net-work in the State of Orissa. Cuttack Station of AIR should be upgraded and modernised by introducing more than one channel.